www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

# देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 214 | जौनपुर बुधवार, 25 मार्च 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

## संक्षिप्त खबरें

### बैलेट पेपर बिल पर विधानसभा में भाजपा का वॉकआउट

बेंगलुरु, (एजेंसी)। कर्नाटक सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की जगह बैलेट पेपर इस्तेमाल करने वाला बिल पेश करके एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। चुनाव कवरेज मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा पेश किए गए श्कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) बिल, 2026श में बैलेट–आधारित मतदान पर वापस लौटने का प्रस्ताव है। इसके पीछे ईवीएम पर जनता का घटता भरोसा और हाल के चुनावों में कथित गड़बड़ियों का हवाला दिया गया है।खड़गे ने तर्क दिया कि बैलेट पेपर से ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। उन्होंने वोटों में अचानक हुई बढ़ोतरी और वोटों की गिनती में विसंगतियों के मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने इन चिंताओं पर चुनाव आयोग की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। इस कदम पर भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। विपक्ष के नेता आर. अशोक ने इस प्रस्ताव को तुगलकी फरमान करार दिया। उन्होंने ईवीएम का बचाव करते हुए उन्हें भरोसेमंद और व्यापक रूप से परखा हुआ बताया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई जांच भी शामिल है। भाजपा के कई नेताओं ने चेतावनी दी कि बैलेट पेपर पर वापस लौटने से चुनावी धांधली फिर से शुरू हो सकती है और कर्नाटक पीछे जा सकता है, खासकर तब जब कर्नाटक एक टेक्नोलॉजी हब के तौर पर जाना जाता है। सदन में तनाव बढ़ने पर भाजपा सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया।

### असम में विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित

गुवाहाटी, (एजेंसी)। असम सरकार ने आगामी असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 9 अप्रैल यानी गुरुवार को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, मतदान के सुचारू संचालन को सुगम बनाने के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत अवकाश घोषित किया गया है। यह निर्णय भारत निर्वाचन आयोग और असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है।अधिसूचना में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), शहरी स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित सभी सरकारी और गैर–सरकारी कार्यालय 9 अप्रैल को बंद रहेंगे। राज्य भर के बैंक, चाय बागान, उद्योग और अन्य प्रतिष्ठान भी मतदान के दिन अवकाश का पालन करेंगे। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के 16 मार्च, 2026 के एक पत्र और उसके बाद असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के 17 मार्च, 2026 के एक पत्र के बाद जारी किया गया था।सरकार ने कहा कि इस उपाय का उद्देश्य नागरिकों को बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देकर अधिकतम मतदाता भागीदारी सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने कहा कि अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित है।

# पश्चिम एशिया संकट देश की बड़ी परीक्षा, साझा प्रयासों से निपटेंगे- पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राज्यसभा में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर केंद्र सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में अलग–अलग क्षेत्रों की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स और अधिकारियों के एंपावर ग्रुप बने थे। इसी तरह कल ही ऐसे सात नए एंपावर ग्रुप का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल– डीजल, फर्टिलाइजर, गैस और महंगाई जैसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे। सरकार ये भी प्रयास

कर रही है कि आने वाले बुआई के सीजन में किसानों को पर्याप्त खाद मिलती रहे। सरकार ने खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। सरकार का निरंतर प्रयास है कि किसानों पर किसी भी संकट का बोझ न पड़े। मैं देश के किसानों को फिर आश्वस्त करूंगा कि सरकार हर चुनौती के समाधान के लिए उनके साथ खड़ी है। पीएम ने कहा कि आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं देश के सभी राज्य सरकारों से भी कुछ आग्रह करना चाहता हूं। संकट के समय गरीबों पर, श्रमिकों पर और प्रवासी साथियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ समय पर मिलता रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां प्रवासी श्रमिक काम करते हैं। उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रो–एक्टिव कदम उठाए जाएं। ऐसी स्थितियों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकारें विशेष व्यवस्थाएं करें, इससे काफी सुविधा होगी। राज्य सरकारों को एक और चुनौती पर भी बहुत अधिक ध्यान देना होगा।

# किसानों की आय में हुआ तीन से चार गुना इजाफा : शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किसानों की आय दोगुनी करने के मुद्दे पर मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार का पक्ष रखते हुए कई अहम बातें कहीं। उन्होंने दावा किया कि देश में कई किसानों की आय दोगुनी ही नहीं, बल्कि कई गुना तक बढ़ी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की आय सिर्फ दोगुनी ही नहीं हुई है बल्कि इसमें दो–तीन गुना तक इजाफा हुआ है और कुछ मामलों में यह आंकड़ा आठ गुना तक बढ़ा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों के समय गांवों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी। उन्होंने कहा, "उस समय न बिजली थी, न पानी और न ही सड़कें थीं।" मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि पहले वहां किसानों को सिर्फ एक ही फसल

मिल पाती थी, क्योंकि बिजली की स्थिति बेहद खराब थी। उन्होंने कहा, "बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। कई बार तो सिर्फ बिजली के बिल ही आते थे।" उन्होंने बताया कि सरकार ने सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई। इसका परिणाम यह हुआ कि आज मध्य प्रदेश में किसान साल में तीन–तीन फसलें ले रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कृषि बजट में बढ़ोतरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले कृषि बजट 19,306 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। अगर कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों को मिलाकर देखा जाए तो कुल बजट 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है।

# उत्तर प्रदेश नवनिर्माण के नौ वर्ष – स्वास्थ्य सेवाओं में `उत्तम प्रदेश' बना देश में अग्रणी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले नौ वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। सरकार ने न सिर्फ स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया, बल्कि डिजिटल हेल्थ, आपात सेवाओं और मातृ–शिशु देखभाल जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। इसके चलते प्रदेश कई स्वास्थ्य मानकों पर देश में अग्रणी बनकर उभरा है। प्रदेश में डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। 5.76 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड तैयार किए जा चुके हैं। माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट के

तहत 35 माइक्रोसाइट्स संचालित हो रहे हैं, जहां 4.4 लाख से अधिक रिकॉर्ड दर्ज कर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। यूनिफाइड डिजीज सर्विलांस पोर्टल के जरिए रोगों की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाया गया है, जबकि 'केयर मॉडल' से अस्पतालों में उपकरणों की उपलब्धता और कार्यक्षमता पर नजर रखी जा रही है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। गर्भवती महिलाओं को निशुल्क अल्ट्रासाउंड के लिए ई–वाउचर की सुविधा दी गई है। जननी सुरक्षा योजना के तहत 13,51,044 लाभार्थियों को फायदा मिला है, जबकि बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 8,79,642 बच्चों का उपचार किया गया है। दस्तक अभियान के माध्यम से एईएस–जेई जैसी बीमारियों के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाया गया। प्रदेश में 22,681 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.31 करोड़ परिवारों के 5.59 करोड़ लाभार्थियों के कार्ड बनाए गए हैं।

# सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान महिलाओं को हर महीने 2500 और छात्राओं को साइकिल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2026–27 के लिए करीब 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य संबंधी जांच, 1.3 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल और मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप सहित कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई। साथ ही आपदा प्रबंधन के लिए 'आपात संचालन केंद्र' के अलावा एक नई सेमीकंडक्टर नीति की भी घोषणा की गई। दिल्ली विधानसभा में दूसरी बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रही गुप्ता ने इसे "हरित बजट" करार दिया और बताया कि कुल आवंटन

का 21 प्रतिशत पर्यावरण संरक्षण पहल के लिए रखा गया है। उन्होंने दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय के देश में तीसरे स्थान पर होने का उल्लेख किया और कहा कि "ट्रिपल इंजन" सरकार के साथ राष्ट्रीय राजधानी तेजी से प्रगति कर रही है। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 19,326 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो कुल बजट का 18 प्रतिशत है। इसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 13,034 करोड़ रुपये, परिवहन के लिए 12,613 करोड़ रुपये, शहरी विकास के लिए 11,572 करोड़ रुपये, सामाजिक कल्याण के लिए 10,537 करोड़ रुपये और जलापूर्ति के लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए कई कदमों की भी घोषणा की और कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुनाव से पहले जिस 'महिला समृद्धि योजना' का वादा किया था वह जल्द लागू की जाएगी। इसके लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए जल्द ही पंजीकरण मंच शुरू किया जाएगा। इस बीच, चार विधायकों के निलंबन के विरोध में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने बजट प्रस्तुति का बहिष्कार किया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उनके फैसले की आलोचना की।

# असम राइफल्स के डीजी ने भारत-म्यांमार सीमा और कश्मीर घाटी में चौकसी बढ़ाने का किया आह्वान

असम, (एजेंसी)। असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने भारत–म्यांमार सीमा और कश्मीर घाटी की सुरक्षा और पवित्रता को बनाए रखने की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बल से उभरती सुरक्षा चुनौतियों और भविष्य की आकस्मिकताओं के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। कल सोमवार को असम राइफल्स कमांडर्स सम्मेलन का आयोजन शिलांग के लैतकोर स्थित असम राइफल्स महानिदेशालय के मुख्यालय में लेफ्टिनेंट जनरल लखेरा की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न फॉर्मेशनों के फॉर्मेशन कमांडरों, बटालियन कमांडरों और स्टाफ अधिकारियों ने भाग लिया। लेफ्टिनेंट जनरल लखेरा ने चुनौतीपूर्ण

परिस्थितियों में भी पेशेवर रवैया और प्रभावी प्रदर्शन करने के लिए सभी रैंकों के कर्मियों की सराहना की। सम्मेलन के दौरान हुई चर्चाओं में परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने, युद्ध की तैयारी को बढ़ावा देने और समग्र दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। चर्चाओं में अगली पीढ़ी के हथियारों और उपकरणों को शामिल करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और प्रशिक्षण एवं कौशल विकास पहलों में सुधार करना भी शामिल था। भारत पूर्वोत्तर चार राज्यों अरुणाचल प्रदेश (520 किमी), मणिपुर (398 किमी), नागालैंड (215 किमी) और मिजोरम (510 किमी) से होकर म्यांमार के साथ 1,643 किमी लंबी बिना बाड़ वाली सीमा साझा करता है। इस संवेदनशील क्षेत्र के अधिकांश भाग की सुरक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है, जिसकी तैनाती जम्मू और कश्मीर में भी है। सम्मेलन के दौरान राजभाषा पहलों के अनुकरणीय कार्यान्वयन के लिए असम राइफल्स राजभाषा शील्ड योजना पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें 23 असम राइफल्स ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसके बाद 28 असम राइफल्स और 34 असम राइफल्स ने क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए। महानिदेशक ने शांति और स्थिरता बनाए रखने में कमांडरों के प्रयासों की सराहना की और गतिशील सुरक्षा वातावरण के बीच उच्च सतर्कता बरतने का आह्वान किया। सम्मेलन का समापन परिचालन उत्कृष्टता के प्रति नवीकृत प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

# नीतीश कुमार जदयू के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए

पटना, (एजेंसी)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को एक बार फिर निर्विरोध रूप से जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। नामांकन के वापस लिए जाने के अंतिम समय गुजर जाने के बाद उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। नीतीश कुमार के अलावा किसी और नेता ने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया। जदयू के राष्ट्रीय सचिव और मुख्यालय प्रभारी मोहम्मद निसार ने एक बयान जारी कर मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जनता दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि मंगलवार 24 मार्च, 2026 को सुबह 11 बजे थी। नामांकन वापस लेने का समय समाप्त होने के बाद, निर्वाचन अधिकारी के पास केवल नीतीश कुमार का नामांकन ही शेष है, इसलिए उन्हें बतौर अध्यक्ष चुन लिया गया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अधिकारी अनिल प्रसाद हेगड़े (पूर्व सांसद, राज्यसभा) आज दोपहर ढाई बजे नीतीश कुमार के निर्वाचित होने का निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी करेंगे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा में संसदीय दल के नेता संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री बिहार सरकार श्रवण कुमार और पार्टी के अन्य

वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने के बाद यह तय हो गया है कि वे राज्यसभा सदस्य के रूप में दिल्ली की राजनीति करेंगे लेकिन पार्टी की बागडोर खुद अपने पास रखेंगे। बता दें कि ललन सिंह के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने यह जिम्मेदारी भी संभाली थी।

# कनोडिया ग्रुप सेल्स प्रमोटर बिग सेम सीमेंट सम्मेलन हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। बुधवार को लखनऊ के गोमतीनगर के होटल मे कानोडिया ग्रुप के द्वारा सेल्स प्रमोटर –बिगसेम सीमेंट का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को कंपनी के सीइओ अनुराग श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए कहा कि इस कम्पनी द्वारा नया आई पी ओ लाने का प्रस्ताव दिया।इस मौके पर उन्होंने कहा इसके साथ ही साथ आने वाले भविष्य मे उत्तर प्रदेश मे कंपनी प्रतापगढ़ मे नया प्लांट डालेगी।सभा को सम्बोधित करते हुए बिजनेस हेड विवेक शर्मा ने भविष्य मे सीमेंट की डिमांड के व कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के भविष्य की चर्चा की।इस मौके पर कार्यक्रम के अंत मे स्टेट हेड राजीव मेहता ने आये हुए अतिथियों को धन्यवाद प्रकट करते हुए कंपनी की तरफ से भेट प्रदान किया।

# केरल कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने भाजपा को घेरा, कहा-एलडीएफ की वापसी में मदद कर रही पार्टी

केरल, (एजेंसी)। केरल में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन केरल में पिनारयी विजयन के नेतृत्व वाली सरकार को बरकरार रखने में मदद कर रहा है। इसके साथ ही कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि एलडीएफ एनडीए के साथ मिलीभगत कर रहा है। पीटीआई वीडियोज को दिए एक साक्षात्कार में, केरल चुनावों के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक पायलट ने मुख्यमंत्री विजयन पर व्यक्तिगत लाभ के लिए, विशेष रूप से भ्रष्टाचार की जांच से बचने के लिए भाजपा के साथ गुप्त रूप से काम करने का आरोप

लगाया। उन्होंने कहा कि माकपा और भाजपा के प्रयास सफल नहीं होंगे क्योंकि लोगों ने उनकी भ्रांति और झूठ को पहचान लिया है। कांग्रेस नेता विजयन द्वारा हाल ही में पीटीआई वीडियो को दिए गए एक साक्षात्कार में लगाए गए आरोपों के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस राज्य में भाजपा की बी–टीम के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा ष्मुझे समझ नहीं आता कि मुख्यमंत्री ऐसे आरोप कैसे लगा रहे हैं? जबकि आंकड़े बताते हैं कि माकपा और एलडीएफ, भाजपा और एनडीए के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। आज भी, केरल चुनावों में एनडीए की भागीदारी पूरी तरह से एलडीएफ की सत्ता में वापसी को आसान बनाने के उद्देश्य से प्रतीत होती है। पायलट ने कहा, ष्भाजपा के पास खोने के लिए कुछ खास नहीं है। उसके पास कुछ क्षेत्रों में वोट हैं, जिन्हें वह वामपंथी उम्मीदवारों की ओर मोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि वे तीसरा कार्यकाल हासिल कर सकें, जो कि होने वाला नहीं है।ष आगे उन्होंने कहा कि वामपंथी सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों से एक साथ काम किया है। उन्होंने माकपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री या भाजपा के खिलाफ कोई प्रदर्शन, विरोध, आंदोलन, याचिका या विरोध नहीं देखा है।

# संपादकीय

## ऊर्जा संकट में फंसा देश

तूफान आने पर रेत में सिर घुसाने की शुतुरमुर्गी प्रवृत्ति कितनी घातक होती है, यह बात अब शायद मोदी सरकार को समझ आ रही होगी। पिछले 12 सालों से देश को सब चंगा सी मोड में डाल कर रखा गया है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए नित नए शिगूफे छेड़ दिए जाते हैं। लेकिन न वादों से पेट भरता है, न शिगूफों से असली समस्याओं का वास्तविक हल निकलता है। इसके लिए काम करने की जरूरत पड़ती है, जो मोदी सरकार ने किया नहीं। बल्कि जो बने–बनाए काम थे, उन्हें और बिगाड़ दिया। जिसका खामियाजा अब जनता भुगत रही है। यही कारण है कि 11 दिन पहले ईरान पर किया गया हमला अब भारत की आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ईरान पर हमले और पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध के प्रभाव के कारण ईंधन आपूर्ति में बाधा आने लगी है, जिससे भारत में एलपीजी संकट गहरा गया है। हालांकि देश को कई बड़े पत्रकार और मीडिया घराने ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ऊर्जा का कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि वहां स्कूलों, कार्यालयों में उपस्थिति 50 प्रतिशत तक घटा दी गई है, और महंगाई बढ़ने का खतरा है। लेकिन पाकिस्तान के बिगड़े हालात दिखाकर हम अपनी मुश्किल आसान नहीं कर सकते। इसलिए जो सच है, उसका सामना करना ही होगा। गनीमत है कि सरकार ने इस दिशा में पहला कदम बढ़ाया है।सरकार ने देश में घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक कुछ क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। इनमें घरेलू पीएनजी सप्लाई, ट्रांसपोर्ट के लिए सीएनजी, एलपीजी, पाइपलाइन कंप्रेसर फ्यूल और आवश्यक पाइपलाइन ऑपरेशनल जरूरतें शामिल हैं। केंद्र सरकार ने गैस बुकिंग का समय 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है।दरअसल इससे पहले देश के कई शहरों में सिलेंडर के महंगे होने और कालाबाजारी की खबरें आने लगीं। सरकार ने तो अपनी तरफ से 60 रूपए घरेलू गैस में 115 रूपए कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ाए हैं। लेकिन उपभोक्ताओं को इनकी कहीं ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है, जो जाहिर तौर पर कालाबाजारी में लिप्त लोगों की देन है। नैशनल रेस्टोरेंट असोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक सरकार ने कहा है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की सप्लाई पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जमीनी सच्चाई अलग है।

## पत्रकारों के साथ अपराधियों जैसा सलूक

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार शाम समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई) के 9 रफी मार्ग स्थित कार्यालय को कथित तौर पर भूमि आवंटन की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में सील कर दिया। देश की सबसे पुरानी समाचार एजेंसी के साथ दिल्ली पुलिस ने जो सलूक किया, उस पर लोकतंत्र के पक्षधर नागरिक चिंता व्यक्त कर रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड, वीमेंस प्रेस क्लब समेत कुछ पत्रकार संगठनों ने भी इसकी निंदा की है और अलग–अलग दलों के कुछ नेताओं ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए हैं। लेकिन इस खबर पर जो व्यापक हलचल मचनी चाहिए थी, वो कहीं नजर नहीं आ रही। इससे समझ आता है कि अब हम शायद जागरुक समाज नहीं रहे, और काफी हद तक संवेदनहीन, आत्मकेन्द्रित हो चुके हैं। तभी तो बड़ी से बड़ी घटनाएं भी हमें विचलित नहीं करतीं। अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं, बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की कई खबरें आती हैं और समाज उन्हें सरसरी निगाह से देखकर टाल देता है कि ये सब तो होता ही रहता है। अत्याचार तो पहले भी होते रहे हैं, तब पत्रकार इन्हें उजागर करना अपना दायित्व समझते थे।क्योंकि जब तक समाज की बुराइयों को सामने नहीं लाया जाएगा, तब तक उनका खात्मा करने के तरीके भी नहीं तलाशे जा सकते। लेकिन अब मीडिया भी उन्हीं खबरों को तरजीह देता है, जो वायरल हों, जिनके कारण टीआरपी बढ़े या लाइक्स और कमेंट्स ज्यादा मिले। यही वजह है कि पहले कुंभ मेले में एक सुंदर युवती मोनालिसा चर्चा में आई, फिर उसके अभिनेत्री बनने की खबरें खूब चलीं और अब उसने विवाह कर लिया तो उस पर भी प्रेस कांफ्रेंस हो गई कि उसने जिस व्यक्ति से विवाह किया, उसका धर्म क्या है और यह सही है या नहीं। सोचिए मीडिया ने अपनी प्राथमिकताओं को किस गर्त में पहुंचा दिया है कि दो बालिग आपसी रजामंदी से विवाह करें तो वह उनकी हेडलाइन्स बन जाती है।इस माहौल में यूएनआई का दफ्तर सील करना और वहां मौजूद पत्रकारों से बदसलूकी आम खबर की तरह आई और चली भी गई। गौरतलब है कि दिल्ली में संसद भवन के पास 9 रफी मार्ग पर लगभग 5,289.52 वर्ग मीटर जमीन दशकों पहले यूएनआई को सरकार ने लीज पर दी थी। इस जमीन की अनुमानित कीमत मौजूदा दर 7.74 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से करीब 409 करोड़ रुपये आंकी गई है। सरकार ने यह जमीन संयुक्त कार्यालय परिसर विकसित करने के यूएनआई को दी थी, लेकिन कम से कम 40 साल बीतने के बाद भी वहां कोई निर्माण नहीं हुआ। सरकार का कहना है कि यूएनआई कार्यालय का निर्माण नहीं कर सका, जो आवंटन पत्र में तय शर्तों का उल्लंघन है। जिसके बाद आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत आने वाले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने 12 जनवरी 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद 29 मार्च 2023 को आवंटन रद्द कर दिया था।न्यूज एजेंसी ने इस रद्दीकरण को अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने वित्तीय कमी और लंबित मंजूरियों को देरी का कारण बताने वाले उसके तर्कों को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि चार दशकों से अधिक समय तक भवन का निर्माण न करना आवंटन की शर्तों का गंभीर उल्लंघन है। शुक्रवार को ही यह फैसला आया और इसी शाम को ही कुछ वकील और दिल्ली पुलिस भारी दलबल के साथ परिसर पहुंच गए।अदालत का फैसला और उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई तो सही है, लेकिन यहां असली सवाल पुलिस के रवैये का है। जिस तरह एक मीडिया संस्थान से कर्मचारियों को निकाला गया, वैसा सलूक अपराधियों के साथ किया जाता है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो आए हैं, जिनमें यूएनआई परिसर में बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं और पत्रकारों–कर्मचारियों से दफ्घ्तर खाली करने को कह रहे हैं। नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि दफ्घ्तर खाली कराने में कघनूनी प्रक्रिया का पालन किया गया और कुछ भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई थी। लेकिन यूएनआई ने अपनी पोस्ट में एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उसके दफ्घ्तर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं और कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ धक्का–मुक्की हो रही है।यूएनआई के कुछ कर्मियों ने बताया कि शाम को कुछ वकील और अधिकारी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अन्य बलों के साथ यूएनआई के दफ्घ्तर पहुंचे। शाम 6 से 6.30 बजे के बीच प्रशासनिक कार्यालय बंद हो चुका था, ये सभी लोग सीधे न्यूज रूम में घुस गए जहां उर्दू और हिंदी सर्विस है। रोजा इफ्घ्तार का समय था तो उर्दू सर्विस के कुछ लोग बाहर गए थे। अधिकारियों ने आते ही कहा कि आप अपने कम्प्यूटर तुरंत बंद कीजिए क्योंकि आपका लीज कैंसिल हो गया है और आपको तुरंत बाहर निकलना चाहिए, पांच मिनट, दस मिनट, सात मिनट...इस तरह वो काउंट डाउन करने लगे। उन्होंने मोबाइल पर पढ़कर आदेश सुनाया कहा कि आपको यह कार्यालय तुरंत खाली करना पड़ेगा क्योंकि इसे सील करवाना है। कर्मियों का कहना है कि हमें जबरदस्ती धकेला गया, महिला कर्मचारियों को खींचा गया। इस तरह से किसी समाचार संगठन को बंद करने की शायद यह पहली घटना है।

# महिलाओं को लेकर डॉ कलाम का सपना अधूरा

योगेंद्र

देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइलमैन के नाम मशहूर रहे डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि महिलाओं का सशक्तिकरण एक अच्छे परिवार, अच्छे समाज और अंततः एक अच्छे राष्ट्र के विकास की ओर ले जाता है। जब महिला सुखी होती है, तो घर सुखी होता है। जब घर सुखी होता है, तो समाज सुखी होता है, और जब समाज सुखी होता है, तो राज्य सुखी होता है, और जब राज्य सुखी होता है, तो देश में शांति होती है और उसका विकास अधिक गति से होता है। देश महिलाओं की मौजूदा हालात को देखते हुए लगता यही है डॉ कलाम का यह सपना पूरा नहीं हुआ है। इस सपने को पूरा करने के लिए अभी शायद दशकों तक इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय महिलाओं ने स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर संसद में नेतृत्व तक का लंबा सफर तय किया है, फिर भी सच्ची समानता अभी भी दूर है। मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, जमीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है और महिला आरक्षण विधेयक एक बड़ी छलांग का वादा करता है। लेकिन लैंगिक भेदभाव, परोक्ष राजनीति और सुरक्षा संबंधी चिंताओं जैसी व्यवस्थागत बाधाएं अभी भी बनी हुई हैं। विश्व स्तर पर भारत में महिलाओं की स्थिति मिश्रित है, जहाँ वे नेतृत्व और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही हैं, वहीं लैंगिक असमानता, सुरक्षा और श्रम भागीदारी में उन्हें गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा और साक्षरता में प्रगति के बावजूद, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और आर्थिक असमानता प्रमुख बाधाएं बनी हुई हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। जो महिलाओं की स्थिति में चिंताजनक गिरावट दर्शाता है। देश में महिलाएं अभी तक लिंगभेद का शिकार हैं। महिलाओं के साथ होने वाले शोषण और अपराधों के ग्राफ बताते हैं कि उनकी तरक्की ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा नहीं है। साल 2023 की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 2023 में महिलाओं के खिलाफ 13,366 मामले दर्ज हुए, जो मुंबई में 6,025 और बेंगलुरु में 4,870 से कहीं ज्यादा हैं। हालांकि साल 2022 के मुकाबले महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 5.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। देश में 2021 से 2023 के बीच महिलाओं के खिलाफ कुल 13,21,745 अपराध दर्ज हुए। औसतन हर तीन मिनट में एक महिला किसी न किसी अपराध का शिकार हुई। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में पेश आंकड़ों के बताया कि ने घरेलू हिंसा, अपहरण, यौन अपराध और बाल शोषण जैसी घटनाओं में लगातार तीन वर्षों में बढ़ोतरी देखी गई। उत्तर प्रदेश इन तीन वर्षों में सबसे आगे रहा, जहां 1,88,207 मामले दर्ज हुए। इसके बाद महाराष्ट्र में 1,31,958, राजस्थान 1,31,246, बंगाल 1,05,313 और मध्य प्रदेश में 95,780 मामलों ने स्थिति की गंभीरता को उजागर किया है। महिलाओं के खिलाफ प्रमुख अपराधों में शामिल रहे पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के 4,09,929 मामले तो वहीं अपहरण के 2,49,284 मामले सामने आए। गृह राज्य मंत्री बंदी ने बताया था कि अपराधों के ये रुझान सामाजिक और कानून–व्यवस्था की चुनौतियों को उजागर करते हैं। विभिन्न राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बच्चों से जुड़े अपराधों की संख्या चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई है। आर्थिक भागीदारी में भारत में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों (82:) की तुलना में केवल 18: है, जो काफी कम है। कामकाजी महिलाओं में से केवल 40–42: ही अपने पति के बराबर या उससे अधिक कमाती हैं। साक्षरता दर में 2010–2021 के बीच 14.4: की वृद्धि हुई है। हालाँकि, केवल 10: महिलाएं अपने स्वास्थ्य संबंधी निर्णय खुद ले पाती हैं। संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। 2024 में 800 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। फिर भी, वैश्विक स्तर पर यह भागीदारी अभी भी कम है। लोकनीति–सीएसडीएस के 2019 के श्महिलाएं और राजनीतिश सर्वेक्षण के मुताबिक अधिकतर महिलाओं को रैलियों में



जाने, उम्मीदवार से मिलने या चुनाव प्रचार करने के लिए परिवार की मंजूरी लेनी पड़ती है। 58 प्रतिशत महिलाओं का मानना था कि राजनीतिक परिवार से आने वाली महिलाओं के लिए राजनीति में प्रवेश आसान होता है। जबकि 57 प्रतिशत का मानना था कि आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों की महिलाओं को बढ़त मिलती है। अपने सर्वोच्च स्तर पर भी पहुंचकर भी महिलाओं का लोकसभा में हिस्सा लगभग 14 प्रतिशत ही रहा, जबकि मतदाताओं में उनकी हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत है। 1952 में पहली लोकसभा में सिर्फ 22 महिलाएं चुनी गई थीं। 1977 में तो यह संख्या घटकर 19 ही रह गई। एक बड़ा बदलाव 21वीं सदी में दिखा। साल 2009 में 59 महिलाएं सांसद बनीं, 2014 में यह संख्या बढ़कर 62 हो गई, और 2019 में यह ऐतिहासिक रूप से बढ़कर 78 तक पहुंच गई। 2024 में यह थोड़ा घटकर 74 रह गई। राजनीतिक दल अक्सर कम टिकट देने को यह कहकर सही ठहराते हैं कि महिलाओं के जीतने की श्संभावनाएंश कमजोर होती हैं। लेकिन सफलता का आंकड़ा इस दावे को सवालों के घेरे में डाल देता है। 1957 में 49 प्रतिशत महिला उम्मीदवार जीतीं, जबकि पुरुषों में जीत का प्रतिशत सिर्फ 33 प्रतिशत था। 1962 में महिलाओं की सफलता दर 47 प्रतिशत थी जबकि पुरुषों की सिर्फ 25 प्रतिशत। हाल के चुनावों में भी महिलाओं की सफलता दर बराबर या थोड़ा बेहतर ही रही। वर्ष 2019 में 11 प्रतिशत जीतीं, जबकि पुरुषों में यह दर 6 प्रतिशत थी। 2024 में महिलाओं की सफलता दर 9 प्रतिशत और पुरुषों की 6 प्रतिशत रही। इन आंकड़ों से साफ है कि जब महिलाओं को टिकट मिलता है तो वे चुनाव जीत सकती हैं। चाहे महिलाएं अब वोटिंग में लगभग बराबरी पर हों, लेकिन असली राजनीतिक शक्ति और प्रतिनिधित्व अब भी सीमित है। महिला आरक्षण बिल का पारित होना इस अंतर को कम करने का एक संरचनात्मक रास्ता जरूर खोलता है। आज भी 23: युवा महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है, जो ग्रामीण और गरीब घरों में अधिक आम है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, पंचायत प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 46: है, " हालांकि, उनकी प्रभावी भागीदारी कम बनी हुई है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों में, जहां अक्सर पुरुष रिश्तेदार निर्णय लेने में हावी रहते हैं।" इस प्रथा को उजागर करने और इसकी निंदा करने के लिए 'प्रधान पति' शब्द राजनीतिक शब्दावली में शामिल हो गया है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार गहरी जड़ें जमा चुके लैंगिक मानदंड प्रगतिशील कानूनों को कमजोर कर सकते हैं दृ परिवार और समुदाय सत्ता में महिलाओं को देखकर असहज महसूस कर सकते हैं, इसलिए वे पुरुषों को पर्दे के पीछे रखकर पुराने मानदंडों को लागू करते हैं। महिलाएं अब सेना, अंतरिक्ष, खेल और व्यावसायिक नेतृत्व में नए मानदंड स्थापित कर रही हैं। स्व–सहायता समूह, डिजिटल साक्षरता और शिक्षा में सुधार के लिए सरकारी प्रयासों से बदलाव आ रहा है। इस गति को बढ़ाने की जरूरत है।

# अमेरिका–ईरान युद्ध से अब इंटरनेट सेवाओं पर संकट के बादल

राजेन्द्र

अमेरिका–इजरायल व ईरान युद्ध के चलते अभी विश्व के देश ऊर्जा संकट का समाधान तो निकाल ही नहीं पा रहे कि डिजिटल सेवाओं के बाधित होने के भय से दुनिया के देशों की सरकारों की जान सांसत में आने लगी हैं। इंटरनेट आज प्रमुख आवश्यकताओं में से एक हो गया है। एयर लाइंस, बैंकिंग सेवाएं, संचार व्यवस्था जिसमें संवाद कायम करने से लेकर सभी तरह की डिजिटल सेवाएं, स्टॉक मार्केट आदि आदि बुरी तरह से प्रभावित होने की संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता। आज इंटरनेट पर निर्भरता बहुत अधिक हो गई है। अमेरिका–ईरान युद्ध को जिस तरह से शुरुआती दौर में ट्रंप द्वारा हलके में लिया जा रहा था वास्तव यह ट्रंप की गलत फहमी ही रही। वैसे भी रुस यूक्रेन के युद्ध से ही अमेरिका को सबक लेना चाहिए था। दोनों देश पास पास होने और संसाधनों की दृष्टि से रुस अधिक ताकतवर होने के बावजूद आज तक कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा। अमेरिका ईरान युद्ध के साइड इफेक्ट के रुप में अभी तो उर्जा संकट है पर जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं आने वाले समय में मध्य पूर्व के देशों में पेयजल और दुनिया के देशों के लिए इंटरनेट सेवाओं के प्रभावित होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। दरअसल जिस तरह से कच्चे तेल और एलपीजी आदि की दुनिया के देशों में सप्लाई हार्मुज जलडमरुमध्य के रास्ते होने और ईरान द्वारा इस रास्ते में अवरोधा बनने से उर्जा संकट गंभीर रुप लेता जा रहा हैं। ठीक यही समस्या इंटरनेट को लेकर हो सकती है। कारण साफ है। युद्ध समाप्ति या यों कहें कि सीज फायर के आसार अभी तक बनते नहीं लग रहे तो दूसरी और ज्यों ज्यों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के अधिक प्रयास होंगे तो ईरान हथियार के रुप में समुद्र में बिछी केबल्स को भी नुकसान पहुंचाने में कोई गुरेज नहीं करेगा। दुनिया के इंटरनेट ट्रैफिक का प्रमुख रास्ता भी यही है। एक मोटे अनुमान के अनुसार 20 प्रतिशत ट्रैफिक हार्मुज और लालसागर के रास्ते से गुजरता है। हार्मुज जलडमरुमध्य तो हालात यहां तक है कि सकरे स्थान पर तो मात्र 200 फीट की गहराई पर ही सबमैरिन केबल लाईने बिछी हुई है। लगभग यही हालात लालसागर के हैं। वहां भी इंटरनेट सेवाओं के लिए सबमैरिन केबल्स बिछी हुई है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ईरान द्वारा हार्मुज जलडमरुमध्य क्षेत्र में सुरंगे बिछाने का काम किया जा रहा है और इससे अन्य नुकसान होने के साथ ही फाइबर केबल्स के भी क्षतिग्रस्त होने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। अधिकांश प्रमुख सेवा प्रदाताओं ने इसी क्षेत्र में डेटा सेंटर स्थापित कर रखे हैं। जानकारों के अनुसार हार्मुज क्षेत्र से करीब 20 और लालसागर क्षेत्र से 17 केबल्स गुजरती है। 2024 में भी लाल सागर क्षेत्र में हूती हमलों के दौरान केबल प्रभावित हो चुकी है। वर्तमान हालातों में यदि सबमैरिन केबल्स प्रभावित भी होती है तो हालात जिस तरह के हैं उनमें प्रभावित केबल्स को ठीक करनों में महीनों ही क्या साल भी लग सकता है और ऐसे में दुनिया के देश एक नए संकट के दौर से गुजरने को मजबूर हो जाएंगे। इंटरनेट की दुनिया अभी छह दशक भी पूरे नहीं कर पाई है कि बड़ी समस्या सामने आ गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 1960 में जब जेसीआर लिकलाइडर ने वैश्विक नेटवर्क की कल्पना की थी उस समय यह सोचा भी नहीं होगा कि तीन से चार दशक में ही इंटरनेट संचार जगत में बड़ी क्रांति लाने में सफल हो जाएगा। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा एंडवास्ड रिसर्च प्रोजेक्टस एजेन्सी नेटवर्क के लिए विंट सर्फ और बॉब काह्न ने टीसीपीध्आईपी प्रोटोकाल विकसित किया। इंटरनेट की दुनिया में आमूलचूल बदलाव तो टिम बर्नर्स ली द्वारा ड्ब्लूड्ब्लूड्ब्लू वर्ल्ड वाइड वेव विकसित किया तो इससे संचार दुनिया ही बदल गई। भारत में सही तौर पर तो 1995 में वीएसएनएल ने इंटरनेट सेवाओं का विस्तार किया। आज बड़ी समस्या यह है कि अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि के विशाल डेटा सेंटर यूएई और सउदी आदि देशों में हैं। यही कारण है कि समुद्री रास्ते से फाइबर केबल्स भी हार्मुज जलडमरुमध्य व लालसागर होते हुए ही हैं। यदि केबल्स में व्यवधान होती है या किसी तरह से जाने अनजाने नुकसान पहुंचता है तो वीडियों काल, ईमेल आदि से लेकर इंटरनेट से जुड़ी सभी तरह की सेवाएं प्रभावित हो सकती है और इसीको लेकर चिंता की लकीरें खिंचने लगी है। वैसे आज संयुक्त राष्ट्र संघ तो बेमानी हो गया है। दुनिया के देशों के अलग अलग बने संगठन चाहे वे नाटो हो या ब्रिक्स या पिछले कुछ सालों के देश–दुनिया के हालातों में बेमानी हो गए हैं। वैश्विक हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि कोई ना कोई ऐसी नियामक संस्था या कोई ना कोई इस तरह की बाधयकारी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए जिससे दुनिया के देशों और उनके नागरिकों से जुड़ी सुविधाओं से छेड़छाड़ ना हो इस तरह की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। किसी भी देश या संगठन को इस तरह की सार्वभौमिक सेवाओं को बाधित करने से रोकने की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया के देशों में कौन कब सिरफिरा नेता अपने अहम् की शांति के लिए दुनिया को संकट में ड़ाल दे इसकी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। आज ऊर्जा, पानी, स्वास्थ्य, डिजिटल दुनिया आदि आदि ऐसी सेवाएं है जिनके प्रभावित होने का असर समूची नहीं तो अधिकांश देशों पर पड़ता है और यह दुष्प्रभाव केवल देशों तक ही नहीं अपितु वहां निवास करने वाले करोड़ों नागरिकों पर सीधे सीधे पड़ता है। ऐसे में पूरी वैश्विक व्यवस्था को ही ठप्प करने वाले प्रयासों पर अंकुश या कारगर रोक लगाया जाना जरुरी हो जाता है। दो देशों के टकराव के चलते समूची दुनिया या दुनिया के अधिकांश देशों को संकट में नहीं ड़ाला जा सकता। दुनिया के देशों को इस दिशा में ठोस पहल करनी ही होगी।

# मोदी युग में भारत वाकई बदला मगर गया तो पीछे

राजेंद्र

इन चुनावों में खुद भाजपा के अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता तक बिल्कुल बेरोजगार हैंकृचुनाव में उनकी उपस्थिति तो उनके मुस्लिम–विरोधी तेवर को कमजोर जो कर देगी। सच है कि मोदी युग ने भारत को इतना बदल दिया है कि उसे पहचानना ही मुश्किल हो गया है। पहले भी सांप्रदायिक ताकतें हुआ करती थीं, सांप्रदायिक गबड़बड़ियां भी हुआ करती थीं, शासन के आचरण में भी थोड़ा–बहुत पक्षपात भी हो सकता था, लेकिन शासन और राज्य की मुद्रा आमतौर पर निष्पक्ष होती थी।आखिरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया रिकार्ड कायम कर लिया। मोदी के शीर्ष मंत्रिमंडलीय साथियों की प्रशस्तियों से पूरे देश को यह रिकार्ड बनने का पता चला। यह रिकार्ड है देश में सबसे लंबे समय तक सार्वजनिक पद (वास्तव में मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पद) पर रहने का। इस 22–23 मार्च को नरेंद्र मोदी को उच्च सार्वजनिक पदों पर रहते हुए 8,931 दिन हो गए। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने पवन चामलिंग का रिकार्ड तोड़ दिया, जो 24 वर्ष तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे। पवन चामलिंग का मुख्यमंत्री का कार्यकाल, 8,930 दिन का ही था। नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था और 2014 की 26 मई से प्रधानमंत्री के पद पर हैं। और नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के पद पर रहकर गुजरात को और प्रधानमंत्री के पद पर रहकर देश को जिस दिशा में आगे बढ़ाया है, उसमें बहुत ही मुखर निरंतरताएं हैं। इसलिए, इस रिकार्ड के बहाने 24 वर्ष के नरेंद्र मोदी के इस पूरे कार्यकाल की ही, जिसे श्सेवाश का रिकार्ड बताने पर मोदी के मंत्रिमंडलीय साथियों का खास जोर रहा है, कुछ विशेषताओं को यहां रेखांकित करना अनुपयुक्त नहीं होगा।मोदी के बाद नंबर दो माने जाने वाले, अमित शाह ने गोल–मोल प्रशस्तियों को दोहराने के साथ ही, इनसे कुछ आगे भी जाने की कोशिश की है। यह कहने के बाद कि श्सेवा के मोदीजी के दशक अपना ही एक युग बन गए हैंश, शाह एक्स पर अपनी पोस्ट में इस युग में हुए मुख्य बदलाव भी गिनाते हैं। श्चाहे गरीबों को उनके अधिकार देना हो, चाहे विकास के नये मानक कायम करना हो या वैश्विक मंचों पर राष्ट्र्र का गौरव बढ़ाना हो, मोदी युग ने भारत को इतना बदल दिया है कि इसको पहचानना ही मुश्किल है।श शाह ने अपने बयान के आखिर में संभवतरू अनजाने में जिस एक बड़ी सच्चाई को उगल दिया है, उससे हम भी पूरी तरह सहमत हैं। वाकई श्मोदी युग ने भारत को इतना बदल दिया है कि इसको पहचानना ही मुश्किल है।श आइए, अब जरा इस पर भी तो नजर डाल लें कि मोदी युग ने भारत को किस तरफ इतना बदला है कि पहचान में ही नहीं आता है।मोदी युग के भारत की बदली हुई पहचान का एक पहलू, सचमुच खुद को भारतीय मानने वाले हर देशवासी को जरूर चुभा होगा। अभी गुजरी ईद पर एक ओर तो प्रधानमंत्री ने अपनी मुबारकबाद दी और दूसरी ओर इसी ईद के गिर्द कम से कम पांच खबरें बिना किसी प्रयास के स्मृति में गढ़ी रह गयीं। पहली खबर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से थी, जहां गंगा में एक नाव पर रोजा–इफ्तार करने के लिए, 14 मुस्लिम नौजवानों को शुरूआती तौर पर 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। भाजपा युवा मोर्चा के एक नेता की शिकायत पर पहले गंगा पर नाव में बिरयानी खाकर धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया, फिर बिरयानी खाकर श्हड्डियां गंगा में डालने का और अंत में मल्लाह की नाव जबरन छीनकर ले जाने का। इसी के पीछे–पीछे दूसरी खबर आई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के क्षेत्र, गोरखपुर से। यहां पुलिस ने एक खुली जगह पर इफ्तार करने के बाद, चार नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बिरयानी खाकर, श्हड्डियां एक नाले में डाल दी थीं। नाला एक मंदिर के करीब था और मंदिर के पुजारी की शिकायत थी कि बिरयानी की श्हड्डियां डालकर, उस नाले का पानी दूषित कर दिया गया, जिस नाले से मंदिर के लोग पानी पीते थे, जिस पानी में खाना बनाते थे और जिस पानी से देव प्रतिमाओं को स्नान कराते थे!जरा और बाद में उत्तर प्रदेश में ही मैनपुरी में तथा एक अन्य जगह से, पुलिस अधिकारियों के ईद पर सामूहिक नमाज के लिए इकऋड्ढे हुए लोगों को अकारण धमकाने–धौंस देने के वीडियो वायरल हुए। पांचवीं खबर, राजधानी दिल्ली में उत्तम नगर से थी, जहां उच्च न्यायालय के आदेश पर पुलिस की बहुत भारी तैनाती के बाद और दर्जनों की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश के लिए गिरफ्तारी के बाद, ईद का शांति से निकल जाना, सब के लिए राहत की एक बड़ी खबर बन गया। हिंदुत्ववादी योद्घा लगातार यहां ईद पर खून बहाने की धमकियां दे रहे थे। याद रहे कि यह तो सिर्फ बानगी है। अल्पसंख्यकों के धार्मिक त्यौहारों को तथाकथित हिंदुत्ववादियों द्वारा झगड़े और इकतरफा पुलिस–प्रशासनिक कार्रवाइयों का मौका बनाया जाना, मोदी युग के भारत में जैसे नियम ही बन चुका है। इससे पहले, क्रिसमस पर भी जगह–जगह हमलों तथा गड़बड़ी की खबरें आई थीं। मोदी युग में अल्पसंख्यकों में मुसलमान खासतौर पर निशाने पर हैं, लेकिन ईसाई और यहां तक कि सिख, जैन तथा बौद्घ भी, सुरक्षित कोई नहीं है। यह बढ़ता सांप्रदायीकरण, मौजूदा सत्ताधारियों द्वारा सचेत रूप से फैलाया जा रहा है और राजसत्ता समेत सभी उपलब्ध औजारों का इस्तेमाल कर के फैलाया जा रहा है। राजसत्ता के समाज के संप्रदायीकरण के लिए सुनियोजित इस्तेमाल का इतिहास, उस मोदी युग जितना ही पुराना है जिसकी बात अमित शाह करते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के गुजरात में सत्ता संभालने के चंद महीनों में ही, गुजरात का 2002 का कुख्यात दंगा हो चुका था, जो वास्तव में प्रशासन की शह से, संघ परिवार द्वारा अंजाम दिया गया, मुस्लिमविरोधी नरसंहार ही था। इसके कुछ ही महीने बाद, इस नरसंहार को ही अपना शुभंकर बनाकर नरेंद्र मोदी ने चुनाव में भाजपा को जीत दिलायी और तब तक गुटों में बंटी रही गुजरात भाजपा में अपनी स्थिति सबसे मजबूत कर ली।मोदी युग में वक्त के साथ सांप्रदायीकरण का यह खेल ज्यादा से ज्यादा बढ़ता तथा ज्यादा से ज्यादा खुलेआम ही होता गया है। इसी क्रम में 2024 के आम चुनाव के समय से, खुलेआम मुस्लिमविरोधी दुहाई का सहारा लेने को नरेंद्र मोदी ने खुद ही अपना प्रमुख हथियार बना लिया है। अपनी



मुस्लिमविरोधी पहचान को स्थापित करने के लिए वह पहले श्तुष्टिकरणश–विरोधा की जिस शब्दावली का सहारा लेते थे, उसे छोड़कर अब उन्होंने श्घुसपैठियोंश के खतरे की शब्दावली को पकड़ लिया है। विशेष रूप से झारखंड, एक हद तक महाराष्ट्र्र और पिछले ही दिनों बिहार के चुनाव में श्घुसपैठियों के खतरेश के नारे को जमकर भुनाने के बाद, अब खासतौर पर असम तथा प. बंगाल के चुनाव में संघ–भाजपा सबसे ज्यादा इसी नारे के सहारे हैं। नतीजा यह है कि इन चुनावों में खुद भाजपा के अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता तक बिल्कुल बेरोजगार हैंकृचुनाव में उनकी उपस्थिति तो उनके मुस्लिम–विरोधी तेवर को कमजोर जो कर देगी। सच है कि मोदी युग ने भारत को इतना बदल दिया है कि उसे पहचानना ही मुश्किल हो गया है। पहले भी सांप्रदायिक ताकतें हुआ करती थीं, सांप्रदायिक गबड़बड़ियां भी हुआ करती थीं, शासन के आचरण में भी थोड़ा–बहुत पक्षपात भी हो सकता था, लेकिन शासन और राज्य की मुद्रा आमतौर पर निष्पक्ष होती थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री की हैसियत से अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2002 के नरसंहार के बाद मुख्यमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी को उनका यही श्राजधर्मश याद दिलाया था। पर मोदी युग में, सांप्रदायिक भेदभाव ही राजधर्म है! मोदी युग में कुछ और भी बदला है, जिसने उस भारत को पहचानना मुश्किल बना दिया है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ 100 साल से ज्यादा लड़कर, आजादी हासिल की थी। इस लड़ाई से बनी इस देश की अपनी पहचान को ही मोदी इस युग ने जिस हिकारत से साथ बदला है, उसका जिक्र हम जरा और आगे करेंगे। पहले, इस लड़ाई से निकली आम जनता यानी किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटे व्यवसायी आदि की केंद्रीयता की याद दिला दें, जिसे मोदी युग में पूरी तरह से गायब ही कर दिया गया है।

# निःशुल्क चिकित्सा से वंचित सेवानिवृत्त शिक्षकों ने किया प्रदर्शन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति के बैनर तले बुधवार को सैकड़ों पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस दौरान पेंशनरों ने केंद्र सरकार के एक वित्त अधिनियम पर भी चिंता व्यक्त की। पेंशनरों का कहना है कि प्रस्तावित अधिनियम पेंशनभोगियों का वर्गीकरण कर उनके बीच भेदभाव पैदा करेगा। आरोप है कि इसे बिना पूर्व सूचना के वित्त विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश कर जल्दबाजी में पारित किया गया। यदि यह लागू हुआ तो पेंशनभोगियों की पात्रता उनकी सेवानिवृत्ति तिथि के आधार पर तय होगी, जिससे पुराने पेंशनरों को वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिल सकेगा। समिति ने कहा कि इससे पेंशनरों को आर्थिक नुकसान होगा, खासकर बढ़ती महंगाई के दौर में यह स्थिति और गंभीर हो सकती है। विभिन्न पेंशनर संगठनों ने इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। इसी बीच, उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी, लेकिन जारी शासनादेश में उन्हें शामिल नहीं किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षकों ने बताया कि वे लंबे समय से राज्य कर्मचारियों की तरह इस सुविधा की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें इसका लाभ नहीं मिल सका है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उन्हें भी योजना में शामिल कर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

# जारी हुआ नए शैक्षिक सत्र का कैलेंडर, एक दिन होगी अंग्रेजी में प्रार्थना तय हुआ परीक्षाओं का समय

लखनऊ, (संवाददाता)। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026–27 का कैलेंडर सोमवार को जारी किया है। इसमें सप्ताह में एक दिन प्रार्थना अंग्रेजी भाषा में करने या किसी विद्यालय में अन्य भाषा प्रचलित हो तो उसमें करने का प्रावधान किया है। विद्यार्थियों में स्क्रीन टाइम कम करने और समाचार पत्र पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से प्रार्थना सभा में रोजाना प्रमुख खबरों को पढ़वाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही कठिन शब्दों के उच्चारण, अर्थ और वाक्य प्रयोग भी बताए जाएंगे। परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि कैलेंडर के अनुपालन के निर्देश सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नए सत्र में विद्यार्थियों को मोबाइल के दुष्प्रभावों और ऑनलाइन गेम्स के कुप्रभाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में नया सवेरा कार्यक्रम के तहत शिक्षा अधिकारी विद्यालयों में दो दिन प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों से जीवन मूल्यों, अनुशासन, कॅरिअर और दिनचर्या पर संवाद करेंगे। इसमें अभिभावकों और पूर्व छात्रों को भी आमंत्रित किया जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए हैंड्स–ऑन एक्टिविटीज, एक्सपीरिएंशियल लर्निंग, वैज्ञानिक प्रयोग, गणितीय खेल और प्रयोगशाला गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में एक दिन योग और ध्यान का आयोजन भी किया जाएगा। सभी विद्यालयों में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों से ही पठन–पाठन कराया जाएगा। इसके अलावा साइबर क्लब और बालिकाओं के लिए शक्ति मंच का गठन भी किया जाएगा।

# एचआईवी/एड्स पर राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला आयोजित

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा सोमवार को राज्य सूचना विभाग के सभागार, लखनऊ में एचआईवीध्एड्स विषय पर राज्य स्तरीय मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य एचआईवीध्एड्स से संबंधित सही जानकारी का प्रसार करना, सामाजिक कलंक को कम करना तथा जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों में मीडिया की सकारात्मक भूमिका को सुदृढ़ करना था।कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक रमेश श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक डॉ. संजय सोलंकी सहित सूचना विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के अधिकारियों ने मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित किया। संयुक्त निदेशक रमेश श्रीवास्तव ने कहा कि एचआईवीध्एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथ्यात्मक और संवेदनशील रिपोर्टिंग के माध्यम से समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है तथा लोगों को जांच और उपचार सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।कार्यशाला में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार भारत में लगभग 25.44 लाख लोग एचआईवी के साथ जीवन जी रहे हैं, जिनमें लगभग 45 प्रतिशत महिलाएं तथा लगभग 2.75 प्रतिशत बच्चे शामिल हैं। देश में अधिकांश संक्रमण असुरक्षित यौन संबंध के माध्यम से होता है, जबकि कुछ राज्यों में संक्रमित सुई और सिरिंज के उपयोग से भी संक्रमण के मामले सामने आते हैं।उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लगभग 1.38 लाख एचआईवी संक्रमित व्यक्ति एआरटी केन्द्रों पर निःशुल्क परामर्श, उपचार और दवा प्राप्त कर रहे हैं।

# मोटे अनाज ग्लूटेन–फ्री होने के कारण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं : जिलाधिकारी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में मोटे अनाजों (मिलेट्स) की खेती और उनके उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार को जनपद में एक भव्य 'मिलेट्स रोड शो' का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर इस जागरूकता रैली को रवाना किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों की थाली से दूर हो चुके मोटे अनाजों को पुनः दैनिक आहार में शामिल करने के लिए प्रेरित करना रहा। यह जन–जागरूकता मार्च कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारंभ होकर लाइन बाजार और वाजिदपुर होते हुए कृषि भवन परिसर तक पहुंचा। रैली के दौरान डीजे, प्रचार वाहनों और नारों के माध्यम से आमजन को मोटे अनाजों के पोषण संबंधी लाभों और उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि मोटे अनाज ग्लूटेन–फ्री होने के कारण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। उन्होंने कहा कि इनकी खेती में कम पानी, कम उर्वरक और कम समय की आवश्यकता होती है, जिससे किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने इनकी महत्ता को देखते हुए इन्हें 'श्री अन्न' योजना के अंतर्गत प्रोत्साहित किया है। उन्होंने आगे कहा कि जो अनाज कभी गरीबों का भोजन माने जाते थे, आज वही अपने पोषक तत्वों के कारण आहार विशेषज्ञों और चिकित्सकों द्वारा 'सुपर फूड्स' के रूप में स्वीकार किए जा रहे हैं। सरकार किसानों को मोटे अनाजों के बीज निःशुल्क उपलब्ध करा रही है, जिससे उनकी खेती को बढ़ावा मिल सके। कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक डॉ. वीबी द्विवेदी, जिला कृषि अधिकारी विनय सिंह, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी डॉ. स्वाति पाहुजा, उप परियोजना निदेशक आत्मा डॉ. रमेश चंद्र यादव, टीडी पीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. रमेश सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएं और किसान उपस्थित रहे।

# एकमुश्त समाधान योजना 18 अप्रैल से, आवास विकास और एलडीए के डिफॉल्टरों के लिए मौका

लखनऊ, (संवाददाता)। पूरी किस्तें भरने में डिफॉल्टर साबित हुए आवंटियों को राहत देने के लिए आवास विकास परिषद और एलडीए में एकमुश्त समाधान योजना 18 अप्रैल से शुरू हो रही है। तीन महीने तक इसका लाभ मिलेगा। सोमवार को आवास विकास परिषद मुख्यालय में हुई बैठक में तय किया गया कि आवंटियों की सुविधा के लिए एलडीए और आवास विकास परिषद के कार्यालय में काउंटर और हेल्पडेस्क बनाई जाएगी। यहां आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। आवेदन के साथ जमा की जाने वाले पंजीकरण की रकम ओटीएस में समायोजित नहीं की जाएगी। इस योजना से आवंटियों को दंड ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ओटीएस का पैसा भी किस्तों में जमा करने की छूट है। आवास विकास परिषद के उप आवास आयुक्त चंदन पटेल ने बताया कि हर संपत्ति प्रबंधक कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। यहां एक कर्मचारी कंप्यूटर की सुविधा के साथ रहेगा। योजना का लाभ आवंटन, नीलामी व अन्य तरह से आवंटित सभी संपत्तियों पर दिया जाएगा। उप्र. आवास आयुक्त चंदन पटेल ने बताया कि ओटीएस योजना का शासनादेश 20 मार्च को जारी हो चुका है। एक माह तक इसका प्रचार–प्रसार करना है, ताकि लोगों को उसकी जानकारी दी जा सके। जिन आवंटियों ने लगातार तीन किस्तें नहीं जमा की हैं, वे डिफॉल्टर माने जाएंगे। इन्हें ओटीएस का लाभ मिलेगा। ऐसे आवंटियों की सूची तैयार की जा रही है। ओटीएस की रकम 50 लाख रुपये से अधिक है तो एक तिहाई भुगतान 30 दिन में और बाकी तीन द्विमासिक किस्त में छह माह में देना होगा। समय से पैसा न देने पर अतिरिक्त दंड ब्याज के साथ एक माह में जमा करने का मौका मिलेगा।

# 30 मार्च से शुरू होगी गेहूं खरीद, 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय न्यूनतम समर्थन मूल्य

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक के उपरांत कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता में बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग के प्रस्ताव के अनुसार इस वर्ष भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद 30 मार्च, 2026 से प्रारम्भ होकर 15 जून, 2026 तक संचालित की जाएगी।कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य के सभी 75 जनपदों में कुल 6,500 क्रय केंद्र संचालित किए जाएंगे। खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कुल आठ एजेंसियां नामित की गई हैं, जिनमें भारतीय खाद्य निगम, खाद्य एवं रसद विभाग की विपणन शाखा, उत्तर प्रदेश मंडी परिषद, प्रादेशिक सहकारी संघ, प्रादेशिक सहकारी उपभोक्ता संघ, उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण संघ, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ तथा भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस बार कृषि उत्पादक संगठनों और कृषि उत्पादक कंपनियों को भी क्रय एजेंसियों के माध्यम से खरीद की अनुमति दी गई है, बशर्ते उनके खाते में 20 लाख रुपये की धनराशि हो तथा उनका पंजीकरण एक वर्ष पुराना हो।सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उतराई, छनाई और सफाई के मद में 20 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त देने का प्रावधान किया है। इस अतिरिक्त व्यय का लगभग 60 करोड़ रुपये का भार मंडी परिषद वहन करेगी। कृषि मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गेहूं खरीद का लक्ष्य 30 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। किसानों को बिचौलियों के प्रभाव से बचाने के लिए संपूर्ण व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया गया है तथा पंजीकरण के लिए पोर्टल खोल दिए गए हैं।

# मां चौकिया धाम में 40 फीट का लाल फरहरा स्थापित, 90 साल पुरानी परंपरा का भव्य निर्वहन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में चैत्र नवरात्र की सप्तमी के पावन अवसर पर बुधवार को मां चौकिया धाम में राजपूत राठौर परिवार द्वारा 40 फीट ऊंचा लाल फरहरा स्थापित कर लगभग 90 वर्षों पुरानी परंपरा को श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाया गया। इस विशाल फरहरे पर 'जय मां शीतला' अंकित रहता है, जो आस्था और विश्वास का प्रतीक है। इस धार्मिक आयोजन की शुरुआत जौनपुर रेलवे स्टेशन के भंडारी मोहल्ले से होती है, जहां से श्रद्धालु नंगे पांव यात्रा प्रारंभ करते हैं। ढोल–नगाड़ों और जयकारों के साथ यह शोभायात्रा जौनपुर जंक्शन, मील चौराहा और नई सब्जी मंडी होते हुए आगे बढ़ती है। मार्ग में श्रद्धालु पंचमुखी हनुमान मंदिर पर माथा टेकते हुए मां शीतला का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और फिर चौकिया धाम पहुंचते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद श्रद्धालु पूरे विधि–विधान से फरहरे को मां शीतला के गुंबद पर स्थापित करते हैं। इस दौरान हवन–पूजन और भक्ति भाव से दर्शन का आयोजन किया जाता है। मंदिर के महंत विवेकानंद पांडा ने सभी भक्तों को तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया और इस दिव्य आयोजन को 'अद्भुत' बताया। मंदिर अध्यक्ष विकास पांडा समेत पांडा परिवार के सदस्यों ने राजपूत राठौर परिवार का स्वागत करते हुए इस परंपरा को ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण बताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो उठा।

# गर्मी की चेतावनी के उलट प्रदेश में बदला मौसम, ठंडी हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी हुई जारी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। सोमवार को अचानक एक नए कमजोर विक्षोभ के विकसित होने से बादलों की सक्रियता बढ़ी और मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई जैसे कुछ पश्चिमी जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई। इसके असर से ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। 24.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बरेली में सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं 14.5 डिग्री तापमान के साथ अयोध्या और बुलंदशहर में सबसे ठंडी रात रही। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को प्रदेश में कहीं–कहीं बादलों की आवाजाही रहेगी। लेकिन मौसम

लगभग शुष्क रहेगा। वहीं 26 मार्च से एक और विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके असर से पश्चिमी जिलों में फिर से बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से कुछ जिलों में हवाएं भी चल सकती हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 28 मार्च से फिर एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में हल्की से मध्यम बारिश के संकेत हैं। विभाग का कहना है कि मंगलवार से अगले दो दिन धूप की तपिश बढ़ने से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तापमान में तीन से चार डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी लगातार तीन सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर–पश्चिम भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोमवार को जम्मू–कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की चोटियों पर बर्फबारी हुई और हरियाणा, राजस्थान समेत मैदानी क्षेत्रों में गरज–चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। इस पूरे हफ्ते उत्तर–पश्चिम भारत में छिटपुट से लेकर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू–कश्मीर– लद्दाख–गिलगित–बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर 30–50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। कुछ जगहों पर गरज और चमक के साथ बारिश भी हुई। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, इम्फाल, विदर्भ, छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात क्षेत्र और कच्छ में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। असम में कुछ स्थानों पर भारी बारिश (7–11 सेंटीमीटर) दर्ज की गई। विभाग के अनुसार, इस सप्ताह पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी भारत में छिटपुट से लेकर व्यापक वर्षा होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 24 और 27–28 मार्च को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में छिटपुट भारी वर्षा की संभावना है। 23 से 25 मार्च के दौरान कोंकण और केरल के कुछ क्षेत्रों में गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है।

# विश्व क्षय दिवस पर 104 टीबी मरीजों को पोषाहार वितरण, जागरूकता संगोष्ठी आयोजित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। विश्व क्षय दिवस के अवसर पर ठाकुरबाड़ी महिला विकास कल्याण समिति ने मंगलवार को

सिंगरामऊ स्थित गौरीशंकर मंदिर परिसर में एक व्यापक कार्यक्रम का आयोजन कर स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान 104 टीबी मरीजों को पोषाहार वितरित किया गया तथा 'हां, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं' थीम पर संगोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामानंद कटियार ने कहा कि देश की सच्ची उन्नति तभी संभव है, जब समाज की समस्त व्यवस्थाएं सुदृढ़ हों। "भारत माता की जय तभी होगी, जब सम्पूर्ण व्यवस्थाओं की जय होगी," उन्होंने कहा। उन्होंने पर्यावरणीय असंतुलन, प्रदूषण और अस्वस्थ जीवनशैली को टीबी जैसी बीमारियों के बढ़ने का कारण बताते हुए पौष्टिक आहार और स्वच्छता पर जोर दिया। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर खांसने–छींकने के दौरान सावधानी बरतने की अपील की। विशिष्ट अतिथि कर्नल पुष्पेंद्र सिंह कीर्तिचक्र ने अनुशासन और जागरूकता को टीबी के खिलाफ लड़ाई का अहम हथियार बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक सैनिक देश की रक्षा करता है, उसी तरह समाज को भी इस बीमारी से लड़ने के लिए सजग रहना होगा। संस्था प्रमुख डॉ. अंजू सिंह ने बताया कि 2001 में स्थापित संस्था पिछले 25 वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के क्षेत्र में कार्यरत है। संस्था अब तक 6,000 से अधिक मरीजों को टीबी से मुक्त कराने में सहयोग कर चुकी है तथा 20,000 से अधिक मरीजों को पोषाहार वितरित कर चुकी है। साथ ही महिलाओं और किशोरियों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा टीबी के लक्षण, जांच और उपचार पर विस्तृत जानकारी दी गई। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और जागरूकता गीतों के माध्यम से लोगों को टीबी के प्रति सजग रहने का संदेश दिया गया। बड़ी संख्या में चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

# पानी की टंकी तीन महीने से बंद, डीएम ने जल निगम के जेई, एई और एक्सईएन का वेतन काटा

लखनऊ, (संवाददाता)। समाधान दिवस पर गांव सैदापुर में पानी की टंकी के तीन महीने से बंद होने की शिकायत जिलाधिकारी से की गई। इस पर उन्होंने जल निगम के जेई, एई और एक्सईएन को तलब कर फटकार लगाते हुए उनसे जवाब तलब करने और सभी का एक–एक दिन का वेतन काटने के साथ आपूर्ति तत्काल बहाल कराने का भी आदेश दिए। गांव करोरा में कई अपात्रों को वृद्धावस्था पेंशन मिलने का मामला आया। शिकायतकर्ता अनिल कुमार ने बताया कि जांच में मामला सही पाए जाने के बावजूद विभाग ने कार्रवाई नहीं की। इस पर डीएम ने संबंधित अधिकारी को फटकार लगाते हुए अपात्रों के खिलाफ आरसी जारी कर धन वसूली के निर्देश दिए। भसंडा गांव में अन्नपूर्णा राशन दुकान पर बिजली कनेक्शन न होने की शिकायत पर अधिकारियों को तलब किया गया। डीएम ने आपूर्ति विभाग और लेसा के अधिकारियों को तीन दिन में कनेक्शन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मऊ गांव की सरिता दिव्यांग पति दीपक के साथ फरियाद लेकर पहुंचीं। जिलाधिकारी ने दीपक के पास आकर उनकी बात सुनी व पिंक शौचालय पर उसकी पुनः तैनाती का आदेश एसडीएम को दिए। बख्शी का तालाब। मंडौली ग्राम सभा की हटाई गईं पंचायत सहायक अर्चना वर्मा ने संपूर्ण तहसील समाधान

दिवस में नौवीं बार एडीएम राजस्व को शिकायत दी। आरोप लगाया कि उन्हें षड्यंत्र के तहत हटाया गया है, जिसमें प्रधान, सचिव और बीडीओ शामिल हैं। वह मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर जिलाधिकारी, सीडीओ, डीपीआरओ, एसडीएम बख्शी का तालाब को शिकायत दे चुकी हैं। उधर, दौलतपुर पंचायत के ग्रामीण हर घर जल योजना की अव्यवस्था से परेशान हैं। दो महीने से ग्रामीणों को घरों में लगी टोंटी से पानी नहीं मिल रहा है। एसडीएम ने बीडीओ को जांचकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इटौंजा नगर पंचायत के सभासद सत्यम पांडेय ने दुकानों पर कब्जे की शिकायत एडीएम राजस्व से की। जिले की पांचों तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 383 प्रकरण आए। इनमें से 55 का मौके पर निस्तारण किया गया। मोहनलालगंज में 166 में से 31 मामलों का तुरंत निपटारा किया गया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निस्तारण एक सप्ताह में गुणवत्ता के साथ किया जाए। शिकायतकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाए। उन्होंने सभी प्रकरणों की फोटो व वीडियो सहित आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। सदर तहसील में 33 में से चार, बीकेटी में 63 में से 11, मलिहाबाद में 42 में से चार तथा सरोजनीनगर में 79 में से पांच प्रकरणों का निस्तारण किया गया। अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

# महिला पुलिस कर्मियों ने महिलाओ व बालिकाओं को किया जागरुक

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। चैत्र नवरात्रि के मौके पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर तथा मिशन शक्ति फेज 5 के नोडल प्रभारी व एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।इसी कड़ी में बुधवार को जहां जिले के थाना कैंट रुदौली मवई खंडासा कुमारगंज में यह अभियान चलाया गया।उसी कड़ी में कोतवाली नगर क्षेत्र में महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला की देखरेख मे महिला थाना में तैनात उप निरीक्षक ने जिला चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय के साथ–साथ अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर जाकर यह अभियान चलाते हुए महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया।इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने को कभी भी कमजोर ना समझे दुर्गा,चंडी,काली व लक्ष्मी के रूप में ही अपने को जाने।आप सभी को अपना अधिकार जानना चाहिए क्योंकि महिलाओं व बालिकाओं के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार एक से बढ़कर एक महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है।यह बातें रविवार को जिला महिला चिकित्सालय,जिला पुलिस चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर जाकर वहाँ पर महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूक किया।उन्होंने कहा कि आप सभी अपने को अबला न समझ कर एक शक्ति का रूप माने।अपने चौमुखी विकास के साथ–साथ समाज में रहने वाले सामाजिक तत्वों के साथ–साथ कुरीतियों का भी डटकर मुकाबला करें।इस मौके पर उन्होंने शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या योजना ,बाल विवाह मुक्त भारत अभियान और हेल्पलाइन नंबर के बारे में बालिकाओं ध्महिलाओं को जागरूक किया।महिला अपराध संबंधित अपराध के बारे मे अवगत कराया गया व उन्हें किसी भी प्रकार पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया।इस मौके पर उप निरीक्षक सोनी पीआरडी गायत्री,वीरमती,माधुरी सहित अन्य महिला पुलिस कर्मी व महिलाए मौजूद रही।

# अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा शहर की वीआईपी कौशलपुरी कालोनी

अयोध्या। शहर मे सबसे वीवीआईपी कौशलपुरी कॉलोनी मे इस समय चारों ओर समस्या ही समस्या दिखाई दे रही है।ठेकेदारों और लापरवाह अधिकारियों के चलते कौशलपुरी कॉलोनी के लोग गंभीर समस्याओं से भुगत रहे हैं।यहां तक कि सड़कों की टूटे होने तथा नालियों व डक्ट के खुले होने के चलते कॉलोनी वासी गंभीर रूप से चोटिल हो रहे हैं। इस गंभीर समस्या पर इससे संबंधित विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसके चलते कॉलोनी वासियो में आक्रोश है।देखा जाए तो राम मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम बड़े स्तर पर होता है जिसमें राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। वही एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 19 मार्च के अयोध्या आगमन भी पिछले दिनों रामनगरी में हुआ था। जिधर से वह गुजरी और जहां पर उनका कार्यक्रम था उसे तो दुल्हन की तरीके से नगर निगम तथा अन्य विभागों द्वारा सजाया गया था।वही दूसरी तरफ अयोध्या के सबसे वीवीआईपी कॉलोनी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है।देखा जाये तो धर्मनगरी की सबसे प्रतिष्ठित और वीवीआईपी मानी जाने वाली श्कौशलपुरी कॉलोनीश इन दिनों सरकारी सिस्टम की अनदेखी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है।कॉलोनी की बदहाल सड़कों, अधूरे पड़े निर्माण कार्यों और जलभराव की समस्या ने स्थानीय निवासियों का जीना मुहाल कर दिया है। आलम यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी और ठेकेदारों की मनमानी के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले लंबे समय से कॉलोनी में सड़कों और नालियों का निर्माण कार्य चल रहा है,लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण काम को बीच में ही लटका दिया गया है।जगह–जगह खोदे गए गड्ढे और बिखरी हुई निर्माण सामग्री आए दिन हादसों को दावत दे रही है। बुजुर्गों और बच्चों का घर से निकलना दूभर हो गया है।कौशलपुरी के निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आरोप है कि अधिकारियों की शह पर ही ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं और गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है। कॉलोनी के मुख्य मार्गों की स्थिति इतनी जर्जर है कि दोपहिया वाहन चलाना भी जोखिम भरा हो गया है।कॉलोनी के लोगों ने एकजुट होकर कहा की प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करेंगे स्थानीय निवासी ने बताया, ह्से वीवीआईपी कॉलोनी कहा जाता है, लेकिन सुविधाएं किसी पिछड़े इलाके से भी बदतर हैं।टैक्स हम समय पर भरते हैं, लेकिन बदले में हमें सिर्फ धूल और गड्ढे मिल रहे हैं।क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही निर्माण कार्य को सही मानकों के साथ पूरा नहीं किया गया और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

# भतीजे का आरोप- मुख्य आरोपी भागा हुआ, मोहरे हो रहे गिरफ्तार- पुलिस तैनात

गोरखपुर, (संवाददाता)। बरगदवा निवासी प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार चौहान की हत्या के बाद उनका परिवार गहरे सदमे और दहशत में है। सोमवार को घर के नुक्कड़ पर पुलिस का पहरा लगा रहा लेकिन घर के बाहर सन्नाटा पसरा था। पत्नी और रो–रोकर बेसुध रहे। वहीं राजकुमार के बुजुर्ग पिता की हालत नाजुक दिखी। पुलिस सुरक्षा के बावजूद परिवार में दहशत है। परिजन बाहर लोगों से मिलने में कतरा रहे हैं। सोमवार को घर में राजकुमार की पत्नी सुशीला लगातार रो–रोकर बेसुध हो रही थीं। उनके तीन बच्चे सोनम, प्रियंका और युवराज लगातार पिता की याद में रो रहे थे। राजकुमार के बुजुर्ग पिता जंगीलाल की हालत भी बेहद नाजुक दिखी। वह लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। एकलौते बेटे राजकुमार की याद आते ही उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। वहीं, राजकुमार के भतीजे नीरज ने बताया कि हत्या की घटना को एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन पुलिस अब तक मुख्य आरोपी को पकड़ने में नाकाम है। आरोप लगाया कि प्रशासन और पुलिस मुख्य साजिशकर्ता को बचा रही है, जबकि श्मोहरेश और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। नीरज का कहना है कि जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होता, परिवार सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। नीरज ने बताया कि पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। नाबालिग समेत आठ आरोपियों की गिरफ्तारी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन प्रशासन और पुलिस सुरक्षा के बावजूद खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुख्य साजिशकर्ता अभी भी हमारे परिवार को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। परिवार के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मुख्य साजिशकर्ता को जल्द गिरफ्तार करके उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। नीरज ने बताया कि वे लगातार पुलिस से संपर्क में हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार करके पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया जाएगा। फिलहाल परिवार बाहर किसी से मिलने–जुलने से डर रहा है और घर में ही रह रहा है।

# सिलेंडर,डीजल व पेट्रोल पानी के लिए वाहन चालकों की टंकियों पर दिख रही भारी भीड़

राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।सिलेंडर के साथ साथ पेट्रोल व डीजल पाने के लिए शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक गैस एजेंसी तथा पेट्रोल टंकियों पर गैस उपभोक्ताओं तथा वाहन चालकों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है।शहर के कई पेट्रोल टंकियां पर दो पहिया चार पहिया वाहनों के साथ साथ जज, पुलिस, नगर निगम, जेसीबी,डंफर सहित सरकारी वाहनो की लंबी कतार लगी हुई थी।शहर के शक्तिनगर कॉलोनी के समीप स्थित पेट्रोल टंकी,देवकाली बाईपास से पहले कुछ ही दूरी पर जिसमें से एक पेट्रोल टंकी पर काफी वाहनों की लंबी कटारे देखी गई वहीं एक पेट्रोल टंकी बंद मिली।जबकि वजीरगंज स्थित पेट्रोल टंकी पर दो पहिया चार पहिया वाहन की काफी भीड़ देखी गई। इसके अलावा शहर के सिविल लाइन सहादत गंज, नहरबाग, उदया चौराहा, साकेत पेट्रोल टंकी सहित अन्य पेट्रोल टंकियां पर पेट्रोल व डीजल पानी के लिए भारी संख्या में वाहन चालक अपनी बड़ी के आने का इंतजार करते दिखे और यहां तक कहीं–कहीं पेट्रोल टंकी पर मारपीट की भी नौबत आ गई। वहीं कुछ पेट्रोल टंकियां पर ध्100 का ही डीजल व पेट्रोल संबंधित चौकी प्रभारी व अन्य पुलिसकर्मी लोगों को उपलब्ध कराते हुए दिखे।

# रुदौली विधायक ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलकर अपने क्षेत्र के विकास के बारे मे किया अवगत

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।बुधवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर जनपद अयोध्या की रुदौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामचंद्र यादव ने शिष्टाचार भेंट की।मुलाकात के दौरान विधायक ने उप मुख्यमंत्री का कुशलक्षेम जाना और क्षेत्र से जुड़े विभिन्न जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।बैठक में रुदौली क्षेत्र के विकास कार्यों, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, सड़क, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। विधायक रामचंद्र यादव ने क्षेत्र के समग्र विकास हेतु कई प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए,जिन पर उप मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया।इस दौरान रुदौली में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति पर भी समीक्षा की गई और उन्हें और गति देने पर सहमति बनी मुलाकात को क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

# तीन पक्षों ने किया था संपत्ति पर दावा, दत्तक पुत्र है घर पर कब्जेदार– किन्नर समाज ने किया घेराव

गोरखपुर, (संवाददाता)। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूरजकुंड इलाके में सोमवार को किन्नर समाज के लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे किन्नरों ने पूर्व मेयर आशा देवी की संपत्ति को चारों ओर से घेर लिया और मकान के बाहर ताला लगाकर सड़क पर बैठ गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक उन्हें मकान का कब्जा नहीं मिलता, वे वहां से नहीं हटेंगे। प्रदर्शन के चलते इलाके में हलचल बढ़ गई और आसपास के लोग भी एकत्र हो गए। मामला वर्ष 2013 का है, जब गोरखपुर की पूर्व मेयर आशा देवी (अमरनाथ यादव) का निधन हुआ था। उनके निधन के 24 घंटे के भीतर ही तीन पक्षों ने संपत्ति पर दावा किया। दत्तक पुत्री मधु और दामाद अशोक यादव ने खुद को वारिस बताया, जबकि सगे भाइयों ने पारिवारिक अधिकार जताया। वहीं, किन्नर समाज ने परंपरा के आधार पर संपत्ति पर अपना दावा किया। विवाद बढ़ने पर प्रशासन ने संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए थे। बाद में कोर्ट के आदेश के अनुसार मकान किन्नर समाज के नाम दर्ज हुआ, लेकिन आशा देवी के दामाद अशोक यादव अब तक मकान खाली नहीं कर रहे हैं। इसी कारण विवाद जारी है। किन्नर समाज ने चेतावनी दी है कि कब्जा न मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे और तेज किया जाएगा। गुरु नैना किन्नर के अनुसार, हाल ही में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए पुलिस को कब्जा दिलाने का निर्देश दिया है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है।

# शहर की कई कॉलोनियों में खाली पड़े जर्जर मकान अपराधियों के लिए बने हैं शरणागृह

अयोध्या।शहर मे कई ऐसी कालोनियां मे मकानों के खाली होने और संबंधित मकान के स्वामियों द्वारा ध्यान न दिए जाने के चलते अधिकतर मकान जर्जर अवस्था में तब्दील हो चुके है।जो अपराधियों व आवंछनीय तत्वों के लिए शरणागृह बने हैं।देखा जाये तो इन खाली मकानों मे देर शाम से आवंछनीय व आपराधिक किस्म के लोग रुक कर आसामाजिक कार्य व अपराधिक घटनाओं से संबंधित योजनाए बनाते है।वहीं यहां पर रह रहे स्थानीय लोगों की माने तो इन जगहों पर कई तरह की आपराधिक तथा अनैतिक कार्य संबंधित मकान के स्वामियों के न रहने के चलते और खाली पड़े होने के कारण होते रहते हैं।जिसके चलते आसपास का माहौल खराब हो रहा है।देखा जाये तो शहर के अंजनी पुरम कॉलोनी, सरस्वती पुरम कॉलोनी,नहरबाग, रेलवे कॉलोनी,मोदहा,काशीराम कॉलोनी सहित अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कॉलोनियों के अलावा आवास विकास परिषद की कई ऐसी कालोनियां हैं जहां पर वर्षों से मकान खाली पड़े हैं। जो कि खड़हर के रूप में तब्दील हो गए हैं।वहीं शहर के कई ऐसे मोहल्ले भी हैं जहां पर इस तरह के मकान में आवांछनीय तत्व के लोग रहकर अपराधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं।इसमें सबसे अधिक विकास प्राधिकरण की कई ऐसी कालोनियां हैं।जहां पर लोगों के नाम तो मकान आवंटित हो गया है लेकिन उसे मकान के स्वामी खुद न रहकर उसे खाली छोड़ दिए हैं जो जर्जर अवस्था में तब्दील हो चुका है और वहां पर को किसी के न रहने पर इस तरह के आवांछनीय तत्व अपना डेरा देर शाम से ही जमा लेते हैं।जिसके चलते वे आए दिन कोई ना कोई अपराधी गतिविधियां करते रहते हैं।इस संबंध में यहां के कई स्थानीय लोगों ने बताया कि जिसके चलते यहाँ पर रहने वाले निवासी अपने को भयभीत महसूस करते हैं। परंतु इस गंभीर समस्या पर इससे संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी चुप्पी साधे हुए हैं।जिसके चलते स्थानीय लोगों में इनके प्रति आक्रोश प्राप्त है।इस संबंध में सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि संबंधित क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक,थानाध्यक्ष व चौकी प्रभारी के माध्यम से इस तरह के मकान पर चेकिंग अभियान चलाया जाता है और उस दौरान जो भी व्यक्ति अपराधिक गतिविधियों में पाया जाता है उसके खिलाफ पुलिसिया कार्यवाही भी की जाती है।

# हाईस्कूल पास इटावा का प्रीतम खुद को बताता था अधिकारी, गोरखपुर की युवती से की थी शादी

गोरखपुर, (संवाददाता)। इटावा के इकदिल इलाके के प्रीतम ने खुद को आईएएस अधिकारी के तौर पर बताकर गोरखपुर के एक परिवार को झांसा दिया और घर की बेटी से शादी कर ली। लेकिन संदेह पर परिवार वालों ने इटावा जाकर मामले की तस्दीक की तो पूरी कहानी फर्जी निकली। गोरखपुर में परिवार ने कैंट थाने में आरोपी प्रीतम के खिलाफ केस दर्ज कराया। इसी मामले में पुलिस ने आरोपी प्रीतम को जालौन जिले से गिरफ्तार कर गोरखपुर लेकर आ गई। शहर की युवती से शादी करने वाला फर्जी आईएएस प्रीतम हाईस्कूल पास है। आरोपी किराए के मकान को अपना बताकर शादी रचाई थी। दूल्हे का असली रूप सामने आया तो वधू पक्ष ने विदाई के तुरंत बाद हंगामा किया और बेटी को अपने साथ लेकर शहर आ गए थे। इसका पर्दाफाश पुलिस की जांच में हुआ। पुलिस के अनुसार, आरोपी प्रीतम निषाद उर्फ लल्लू राम, निवासी अंडवा की मड़ैया (थाना बकेवर), इटावा ने गोरखपुर के परिवार को अपने झूठे आईएएस होने का भरोसा दिलाया। उसने इकदिल के लुधियात मोहल्ले में किराये के मकान को अपना बंगला बताकर वधू पक्ष को गुमराह किया। वधू पक्ष की चचेरी बहन रश्मि ने बताया कि घर देखने गए समय युवक ने मकान और संपत्ति को अपना बताकर परिवार को पूरी तरह धोखा दिया।

## संक्षिप्त खबरें

### सलाना उर्स में पढ़ा गया फातिहा, चादरपोशी कर मांगी गई मुराद

भदोही, (संवाददाता)। जयरामपुर स्थित नूरबाग में दरगाह हजरत बाबा नूर आलम सहा का सालाना दो दिवसीय उर्स अकीदत और भाईचारे के साथ सकुशल संपन्न हो गया। उर्स के दूसरे दिन भी रात तक जायरीनों की भारी भीड़ रही। उर्स के समापन पर अकीदतमंदों ने दरगाह पर हाजिरी लगाकर चादरपोशी की। अपनी–अपनी मुरादों के लिए दुआ मांगी। पूरे उर्स के दौरान धार्मिक कार्यक्रमों की शृंखला जारी रही। इसमें कुरानखानी, फातिहा और दुआओं का विशेष आयोजन किया गया। उर्स के मौके पर श्रद्धा और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। जहां हर वर्ग और समुदाय के लोग एक साथ नजर आए। उर्स के आयोजक सज्जादा एवं गद्दी नशीन सूफी शफीक अहमद शम्सी कादरी के नेतृत्व में आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। उनके साथ अबु बकर, मोइनुद्दीन, ताजुद्दीन, बशीर अहमद आदि लोगों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग किया। उर्स मेले के दौरान सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया। इससे जायरीन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साफ–सफाई, पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराई गई।

### खेल छात्रावासों के लिए जिला स्तरीय फिजिकल टेस्ट में छह अभ्यर्थी पास

भदोही, (संवाददाता)। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में प्रवेश के लिए जिलास्तरीय चयन ट्रायल में सोमवार को छह खिलाड़ियों का चयन हुआ। सोमवार को बालक वर्ग का ट्रायल लिया गया। मंगलवार को बालिकाओं का फिजिकल टेस्ट होगा। 15 वर्ष के वर्ग में चयनित खिलाड़ी 27 मार्च को मंडलीय ट्रायल में हिस्सा ले सकेंगे। उप क्रीड़ाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि 15 वर्ष के बालक वर्ग में कुश्ती, हॉकी और फुटबॉल में चयन ट्रायल के लिए फिजिकल टेस्ट में केवल सात खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इसमें कुश्ती के लिए रेहान अली, हॉकी के लिए अंकुश यादव, लकी मौर्य, आर्यन राय व समर मौर्य तथा फुटबाल के लिए दिनेश यादव चयनित किए गए। उप क्रीड़ाधिकारी ने बताया कि यह उन्होंने पहली बाधा पार की है। मंडलीय स्तर पर चयनित होने के बाद उन्होंने उन्हें प्रदेश स्तरीय कैंप में भाग लेने का मौका मिलेगा।

### 20 मार्च को मंदिर से 30 घंटे चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार

भदोही, (संवाददाता)। पुलिस ने पहलवान वीर मंदिर से 30 घंटे चोरी करने वाले आरोपी सर्वेश गिरी निवासी उपरौठ को उगापुर हवाई पट्टी से गिरफ्तार किया है। आरोपी के दो साथी प्रद्युम गिरी और धर्मेंद्र निवासी उपरौठ मौका देखकर भाग गए। पुलिस ने आरोपी के पास से 18 पीतल का घंटा बरामद किया है। एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि तीनों ने मिलकर 20 मार्च की रात को पहलवान बीर मंदिर से छोटे–बड़े 30 पीतल का घंटे चोरी किया था। पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज करके जांच में जुटी थी। सोमवार को पुलिस को सूचना मिली कि मंदिर से घंटा चोरी करने वाले आरोपी गांव के ही धर्मेंद्र को बेचने की फिराक में है।

### सामादिक न्याय के पक्षधर थे डॉ. राममनोहर लेहिया : प्रदीप

भदोही, (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी की ओर से जिला कार्यालय कंसापुर ज्ञानपुर में सोमवार को समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया की 116वां जयंती मनाई गई। सपा कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत को भी नमन किया। जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा कि समाजवादी समतामूलक सामाजिक न्याय के पक्षधर अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के नायक डॉ. राम मनोहर लोहिया स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और प्रखर समाजवादी चिंतक नेता थे। वे आजादी और सामाजिक न्याय के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। संचालन जिला महासचिव ह्रदय नारायण प्रजापति ने किया। इस मौके पर संतोष यादव, केशनारायण यादव, शैलेश सिंह, सीएल सौरभ, कंचन सोनकर, कमला महतो, सुरेश साहु, सूबेदार विश्वकर्मा, राजन यादव, अखिलेश सोनकर, प्रमोद पाल, धर्मेंद्र कुमार मिश्र पप्पू आदि रहे।

### शहादत दिवस पर भगत सिंह, राजगुरू सुखदेव को किया नमन, दी श्रद्धांजलि

भदोही, (संवाददाता)। फत्तुपुर स्थित प्राइमरी स्कूल में वामपंथी और मजदूर नेताओं ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहादत दिवस मनाया। इस मौके पर वहां लगे उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर नमन किया। लोगों ने शहीदों की शहादत पर श्रद्धांजलि दी। वामपंथी नेता इंद्रदेव पाल ने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव ने देश के लिए अपने जान की परवाह नहीं की। आज हर भारतीय को अपने मन में शहीदों को बसाने का संकल्प लेना होगा। वहां मौजूद दर्जनों लोगों ने बारी–बारी से शहीदों को नमन किया। श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जगन्नाथ मौर्य, राजेंद्र प्रसाद कनौजिया, भुलाल पाल, पंधारी यादव, रंजीत यादव, मुरारी लाल गौड़, भान सिंह, बेचू लाल, ह्रदय लाल यादव, ज्ञान प्रकाश, विजय कुमार पाल, मनोज कुमार, धनंजय यादव, मनोज आदि रहे। उधर, आल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक और अग्रगामी किसान सभा की ओर से सोमवार को औराई के बारीगांव भाना तथा चौरी के अनेगपुर में शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहीदों को नमन किया गया। इस मौके पर गुंजा देवी, जुबैदा, गुंडी, मालती, ज्ञानदेवी, मीना, उर्मिला, साधना, रीता, पार्वती, रेखा आदि रहीं।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।